public sector utmost functional autonomy is required. That applies to banks also. These have to function within the framework of transparency. There has to be adequate accountability. Banking being a very sensitive sector, there should be prudential supervision and that is why the Reserve Bank is there to provide prudential supervision of the banking system.

With no prudentials, outside supervision can be a subsitute for self-policing. I have seen only a few days ago a report published by the British Government with regard to what happened to the Bearings, a very ancient merchant bank, which suddenly evaporated. The moral of this is that if internal control systems are not functioning, you may have a very fine outside supervision system. But, in a world that is so complex, where billions and billions of dollars flow across the exchanges overnight, I think no amount of external supervision is a susbtitute, essential though it is for good housekeeping, for strengthening internal control mechansim. So, we have to walk on both legs. We have to strengthen the internal control system mechanism. At the same time, the Reserve Bank has to be alert to see that we have a proper supervision system and that our banks function subject to prudential regulations. That is the broad approach, Madam, that we have for dealing with the problems of our banking system. Thank you very much, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARADE): Now, the question is:

"That the Bill to amend the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT MOTION

Draft Agriculture Policy Resolution

THE MINISTER FOR AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): Madam, I beg to move:

"That this House do consider the Draft Agriculture Policy Resolution (as modified) laid on the Table of the House on the 14th May, 1993."

उपसभाध्यक्ष जी, आप लोगों की कृपा हुई जो दो साल के बाद आपने समय निकाला। जैसा कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, आपकी कृपा हुई। यह बड़ी कृपा है। बहुत दिनों से यह आशा थी कि आप कुछ आंख खोलेंगे और आपने कृपा आज की है। हर एक चीज का शायद समय होता है। बहुत दिनों से यह ख्याल था कि हम ऐग्रीकल्चर पालिसी, कृषि निति का निर्धारण करेंगे और उसके लिए पहले काफी समय से, एक नहीं दो नहीं, पहले भानु प्रताप सिंह कमेटी और फिर जोशी कमेटी बनी। फिर एक चीज आई और फिर वापस चली गई। उसके पश्चात आपने यह जिम्मा मुझे दिया। मैंने सभी साथियों को, सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया फार्म डीलर्स को बुलाया साइंटिस्ट्स को बुलाया। जितने भी साथ मुझे मिल सके उन सब के साथ सलाह-मशविरा करके, विचार करके हमने एक छोटा प्रारूप तैयार किया...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): किसानों को भी बुलाया या नहीं?

श्री बलराम जाखड़: सब को बुलाया, फारमर्स को बुलाया। जो भी किसानों की संस्थाएं थीं उनको बुलाया। जो अपने को ऊंचे फारवर्ड किसान मानते हैं, उनको भी बुलाया। मैंने कहा कि आइए इसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि कीजिए यह पालिसी मेरी और आपकी नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि यह सब किसानों की

पालिसी है और इस हिसाब से जितना भी योगदान आप दे सकते हैं, दीजिए। मैंने कहा कि आइए आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है, आपके सजेशंस का स्वागत है। आपके जो भी सजेशंस है, उनका स्वागत है। मेरी इसमें कोई बंदिश नहीं है, मैं रुढ़िवादी नहीं हूं, दिमागी तौर पर कोई चीज बंद कर दी हो, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी जो स्टेंडिंग कमेटी है। उसने भी कुछ बातें कही हैं। बात उन्होंने भी वही कही है। उन्होंने कहा है कि विस्तारपूर्वक करो, बढ़ाओ। मैंने एक ही बात कहनी है कि जो कुछ सारी बातें हैं अगर मैं उनको पढ़ कर बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए जो आपके पास ज्ञान है वह आप हमें देंगे। मुझे तो इतना ही कहना है कि यह एक किस्म के प्रारूप दे दिया था कि यह चीजें हमने देखनी हैं। कहां हमने एग्रीकल्चर को ले जाना है, किस प्रकार से उत्थान करना है, किस प्रकार से जमीन की उपजाऊ क्षमता की रक्षा करनी है, कैसे पानी का इंतजाम करना है, कैसे डाइवर्सीफिकेशन करके किसान की आमदनी को बढ़ाना है, किस प्रकार से जैविक रक्षा करनी है, किस प्रकार से इनसेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्ज से बचाव करना है, इंटेग्रेटेड मेनेजमेंट करना है, किस तरह से फिशिंग कल्चर करना है, किस तरह से प्लास्टिक्स को लाना है, किस तरह से हॉर्टीकल्चर का उत्थान करना है। इन सारे कामों को करने के लिए हमने सोच विचार कर के इसका प्रारूप तैयार करके आपके सामने रखा है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान भर में काफी सारे क्लाईमेटिक ज़ोन हैं जिनमें अलाहिदा अलाहिदा मांग समय के अनुसार होती है और सीज़न के हिसाब से होती है। सारा भारतवर्ष एक जैसा नहीं है। पूर्व में कुछ है पश्चिम में कुछ और है, दक्षिण में और उत्तर में कुछ और है। मैकरो से माईक्रो हम करेंगे। उस वक्त हर रीजन में अलाहिदा अलाहिदा इम्पलीमेंटेशन के हिसाब से किस प्रकार से हमें बढ़ाना है। किस प्रकार से नीति निर्धारित के साथ साथ इसे कार्यरूप में परिणत करना है। इस सारे सिलसिले में हमने सोच विचार कर के यह किया है। उस वक्त अलाहिदा अलालहिदा ज़ोन के हिसाब से हम करेंगे। यह प्रारूप रख कर हमने नीति को तैयार किया है। इसमें जैसे आपकी इच्छा हो, आप की समझ में जो बात आती हो, कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको हम दूर करेंगे। मैंने किस प्रकार से किसानों को बरी करवाया है सब टेक्सेशन से, यहां महामना-महामना बैठे हुए हैं, आपके कुबेर हैं, मैंने इनसे कहा कि किसानों के प्रति ऐसी भावना रखिये क्योंकि सीलिंग के हिसाब से उसकी ज़मीन तो बिलकुल कम हो गई है। आपने सन् 1950 में सीलिंग लगा दी थी। उसके बाद भगवान ने और सीलिंग लगा दी क्योंकि तीन पीढ़ियां आ गई। तीन पीढ़ियों में एक बाप के दो बेटे, दो के चार और चार छः या आठ बेटे (व्यवधान) जितने भी है उस हिसाब से भूमि सब में बंटती गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। यह चीज़ आगे चलकर गड़बड़ करेगी क्योंकि किसी वक्त हमें यह सोचना पड़ेगा कि इन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बंट जाने के कारण ज्यादा हम उपज कैसे पैदा करेंगे। एक और देखने की बात है जो मेरे दिमाग में कभी-कभी आती है जो आप सब के लिए सोचना जरूरी है। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना भी करता रहा हूं कि जहां हमारी आबादी 30-32 करोड़ थी आज लगभग 92 करोड़ हो गई है। आखिर पृथ्वी कितना भार वहन कर सकती है, यह हमें सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं हम सारे मिल कर सोचते हैं। मुझे बड़ी चिन्ता होती है क्यों नहीं हम सारी पार्टियां मिल कर एक बात को सोचें कि यह भार हमारे ही सिर पर आएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे, कुछ तो सोचते। चीन सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? लेकिन अकेली पार्टी कोई नहीं करेगी। हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भविष्य में हम सब को कमी उठानी पड़ेगी। डवलप्ड कंट्रीज़ में मैंने देखा है जहां तीन-चार-सात प्रतिशत खेती में काम करते हैं। हमारे यहां 70 प्रतिशत खेती का काम करते हैं। 70 प्रतिशत से और ज्यादा कितने काम करेंगे? इस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को वहां से निकाल कर कृषि से उद्योग के क्षेत्र में लाना पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र में लाने के लिए आप को मुल्क में औद्योगीकरण करना पड़ेगा। इसका डाइवर्सीफिकेशन आफ एग्रीकल्चर, रूपांतर जो हमने किया है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए जिस तरीके से हम करना चाहते हैं हम वह चीज़ पैदा करना चाहते हैं जो बाहर के मुल्क पैदा कर रहे हैं। हॉलैंड जैसा मुल्क जो हमारे एक जिले के बराबर है, 13 बिलियन के फैलावर पैदा कर सकता है तो भारतवर्ष में ऐसे हम पांच सौ हॉलैंड बना सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते जबकि सारी चीज़ें हमारे पास है? आज हमारे गरीब किसान ने नाम पैदा किया है। हम फलों के उत्पादन में दुनियां में दूसरे नम्बर पर थे, अब एफ०ए०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार पहले नम्बर पर फलों का उत्पादन सारी दुनियां में करते हैं दूध में सेकेंड नम्बर पर है। दो तीन साल में हम ऊपर आने वाले हैं। वेजीटेबल्ज़ में दूसरे नम्बर पर है, अगले तीन चार साल में पहले नम्बर पर जाने वाले हैं। लेकिन जो हमारे पास नष्ट हो जाता है जो दो चार सालों में इसके बाद ऊपर जाने वाला है और जो हमारे पास नष्ट भी

होता है उसका भी इलाज है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः आपके साथी सुन नहीं रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ः वे शायद एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र): आपका नम्बर तो ऊपर है पर, पर-कैपिटा कितना है?

श्री बलराम जाखड़ः मैं देखता हूं।

मैं इसी लिए कह रहा हूं कि उसका कैसे होगा। अब 25-26 प्रतिशत जो नष्ट हो जाता है अगर उसको ही रोक लें तो कितना फर्क पड़ता है। इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए यही सोचा कि जस्टीफिकेशन के साथ हमें क्या करना है। इसमें आपका ग्रेडिंग का बंदोबस्त नहीं था, पैकेजिंग का हमारे पास बंदोबस्त नहीं था, फारवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज का कोई बंदोबस्त नहीं था, न प्रोसेसिंग का बंदोबस्त था, न एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे पास एयरपोर्ट या पोर्ट थे, न गाड़ियां आदि थीं। कहीं कोई नजारा आज तक किसी ने सोचा नहीं था। वह भी हमने इस पालिसी में सोचा कि इसको किस तरीके से इस स्तर पर लाकर खड़ा करें जहां हम भी पैसा कमा सकें। मेरे किसान की जेब में भी पैसा जा सके। वह भी सुख की सांस ले सके। यह जो शहर का गांव की जीवन स्तर का अंतर है इसको मिटा सकें। हम भी कुछ कह सकें कि हम भी आजाद भारत के निवासी हैं हमें भी कुछ हक है जीने का। उसको किस तरीके से बराबर किया जाए इसके लिए एग्रोप्रिएट कंसोर्टियम किस हिसाब से करने चाहिए, किस तरह से कोल्ड स्टोरेज करने हैं, किस तरीके से प्रीकूलिंग स्टेशंस लगाने हैं, किस तरीके से हम सिखाएं - इसी हिसाब से मैंने कोशिश की है कि इतना उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च की तरफ जो दिया जाए। इसके उत्थान के लिए हम 400 करोड़ से 1300 करोड़ तक ले गए हैं। डेरी फार्म में 500 से 1300 करोड़ ले गए हैं। इसी प्रकार से साढ़े तीन हजार से साढ़े सात हजार करोड़ एग्रीकल्चर में लिया है। ये सारी बातें निहित करके हमने यह बनाया है कि हम किस प्रकार से नकशा बदल सकते हैं भारत की कृषि का भारत के किसान की जागृति का और उसको आमदनी देने का । ये सारी बातें इसमें निहित की हैं। लेकिन इसमें अगर आपका कहीं भी सुझाव हो तो वह आप दे सकते हैं।

इसी तरीके से सब्सिडी की बात जहां तक आती है मैं किसान को देना चाहता हूं। हमारे कुबेर बैठे हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है सोचने का। देखिए अब कई चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हैं। मैं सब्सिडी नहीं कहता हूं। सब्सिडी तो वह होती है जो मैं मुफ्त में दे दूं। जैसे हम ड्रिप इरीगेशन में, स्प्रिंकलर इरीगेशन में बताते हैं कि कैसे पानी का अच्छा उपयोग करना है पानी नहीं है। दुनिया भर में पानी की कमी आएगी और यह एक बहुत बड़ा मसला होगा। पानी सोने की कीमत रखता है। अभी पिछले दिनों इजरायल के मंत्री आए थे मेरे पास, मिस्टर सुर एग्रीकल्चर के वे बता रहे थे कि 15 साल के बाद इजरायल में हमें रीसाइक्लिड वाटर पीने को मिलेगा। यही हाल यहां होने वाला है। लोग पानी का चक्कर करते हैं। इसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन गलत है। हमें पानी का उपयोग करना है। इस प्रकार से करना है कि उससे सिंचाई भी ज्यादा लेनी है और आमदन भी ज्यादा लेनी है। प्लास्टीकल्चर, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन - इनके लिए 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत जो इसमें लिखा है उसको हमने कार्यरूप में परिणत कर दिया है, प्रेक्टिकल शेप दे दी है कि किस तरीके से हम नक्शा बदलना चाहते हैं। जहां जहां आम आदमी का ताल्लुक है उसको हम 50 प्रतिशत देंगे जहां हरिजन और गिरिजन हैं और जो हमारी बहनें हैं आपके लिए स्पेशल प्रावधान रखा है हमने उपसभाध्यक्ष महोदया और हमने 75 प्रतिशत आपको दिया है जिन-जिन बहिनों के नाम जमीन है उनको 75 प्रतिशत देंगे। इसका अंदाजा क्या होगा। अगर मनमोहन जी पैसे देंगे तो डैम बनेगा..(व्यवधान)

श्रीमती धीरा दास (उड़ीसा): अगर पैसा देंगे तो?

श्री बलराम जाखड़ः देखिए देना मेरे जिम्मे, लेना आपके जिम्मे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): आदिवासियों की जो जमीन है जंगलों में वे फारेस्ट वाले उनको नहीं देते हैं। पहले उसको रेगुलराइज करिए तभी यह जो 50 और 75 प्रतिशत की बात है वह होगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं अभी उसकी बात करता हूं वह भी आपके और हमारे जिम्मे काम है। आपने और हमने करना है।

मैं कहना चाहता था अगर मनमोहन सिंह जी डैम बनवाएंगे, अगर गवर्नमेंट डैम बनवाएगी तो सौ रूपए खर्च होंगे, नहर बनवाएगी तो सौ रूपए खर्च होंगे लेकिन यहां मनमोहन सिंह जी 50 रुपए देंगे और 50 रुपए हम देंगे तो हम एक एकड़ की बजाए दो एकड़ में सिंचाई होगी। स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम पैसा देंगे तो हम एक

एकड़ के बजाए ढाई एकड़ में सिंचाई करेंगे और उसका प्रोडक्शन जो एक एकड़ में दस मन होता है वह होगा उसकी जगह 14-15 मन। तो अंदाजा करिए कि ढाई या तीन, चार, पांच गुना पैदा होगा। यह हम करना चाहते हैं। इस हिसाब से हम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इनको मनवाया और यह बात इन्होंने मानी कि हां यह काम तो ठीक है। इसलिए उन्होंने पैसा दिया है। तो इसलिए इन्होंने पैसा दिया। अगली बार और खुला करके देंगे तो और पैसा दूंगा। लेकिन अभी तक मैं जहां-जहां हर स्टेट में जाता हूं और अभी कल-परसों मैं हैदराबाद उनको कह कर आया हूं, मुझे इस बात को कहते हुए कोई शंका नहीं है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार कहीं भी हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं, जितना पैसा तुम ले सकते हो हिम्मत है इतनी काम करने की किसान को दो। उसका उत्थान होगा। इसी हिसाब से हम करना चाहते हैं। हमने करवाया है। भानु प्रताप सिंह कमेटी ने तो लिखा है कि इंडस्ट्री के उसको बराबर नहीं ला सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बातें हैं कि जहां हम कर सकते हैं। हमने लिखा है कि इंडस्ट्री का दर्जा उसको हम दें और दिया। उसी हिसाब से मैंने उसको खुला किया। पहले तो हमने भारतवर्ष में यह काम किया कि एक स्टेट में, जैसे आप पंजाब में पैदा करो और मद्रास में ले जाओ, तामिलनाडु में ले जाओ, आप केरल में पैदा करो और अरुणाचल प्रदेश में ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां मर्जी आप अपना सामान लेकर चले जाओ। आपको खुली छूट है। सपोर्ट प्राइस के बारे में भी इन्होंने लिखा तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि जो रेम्युनरेटिव होना चाहिए लाभदायक होना चाहिए उसके हिसाब से हमने जितना भी कुछ हो सकता था, वह हमने हमारा जो प्राइस कमीशन है उसको एक-एक चीज में बता कि "ए" से लेकर "जैड" तक हरेक चीज को गिनती कर लो, जमीन ले लो, जमीन की कीमत ले लो, उसका ब्याज ले लो, जो उसके साथ इम्प्लीमेंट्स हैं, बैल है उनका भी लगा लो, बीज कर लो। दवाई कर लो, खाद कर लो, लेबर कर लो उसमें जो भी कुछ कर सकते हो वह कर लो जो कि आपको सही-सही नज़र आए।

श्री जगेश देसाई: स्वयं की लेबर भी।

श्री बलराम जाखड़: हां, स्वयं की लेबर भी साथ में उसको मैंने मैनेजमेंट का भी डाल दिया है, लेकिन हमने किसी बात को छोड़ा नहीं है। इसके अलावा हमने यह भी कर दिया कि जितना ऊंचा बेंच सकते हो बेचो और जहां मर्जी बेचो। आप अंदाजा कर लीजिए तकरीबन-तकरीबन गेहूं और धान के बगैर अब कोई चीज में जरूरत नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की, थोड़ा सा सीरियल्स है, बाकी तिलहन में नहीं, कॉटन में नहीं, ये चीजों में किसी में करने की जरूरत नहीं है। हम तो वह देते हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। फिलहाल आपको भी बता देना चाहता हूं शायद आपको ज्ञान न हो, आपको पता होना चाहिए कि इस साल जिस तरीके से फसल पैदा हुई और रेकार्ड उत्पादन हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार जो रेकार्ड उत्पादन था उससे भी ऊपर ले गए। 19 करोड़ टन अनाज आपने इस साल पैदा किया। अगर सरकार नहीं खरीदती कई लोग तो कहते हैं कि साहब, पैसा नहीं देते, यह नहीं करते, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सरकार क्या करती है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाश भी तो मिलनी चाहिए। किसी ने यह शाबास नहीं दी। 19 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ। बाजार में रुलता रहा। अगर सरकार नहीं खरीदती तो 360 जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं की दी थी, उसको बाजार में ढाई सौ रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं होता। यह सरकार की नीयत है और अगर ऊंचा मिले तो बेंचो। कॉटन का भाव हमने 1200 रुपये दिया। 2300 रुपये बेची है, 24 सौ रुपये बेची है और हमने उसको रोका नहीं कि ऐसा मत करो। तुम बेचो इसको भी हम करना चाहते हैं। इसी हिसाब से वह काम चले। ये सारी बातें इसमें निहित हैं, हमारी पालिसी में है।

इसके साथ-साथ जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसने इसमें और लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसका विस्तार करो। विस्तार के बारे में मैंने कहा तो पोथा बन गया। नार्थ, साउथ, ईस्ट का इसमें फर्क नहीं रहेगा। मुझे सिर्फ छुट्टी दो कि मैं अलाहिदा-अलाहिदा जो जोन्स हैं उनमें अलाहिदा-अलाहिदा उसके कार्यकलाप का कर-कर के यहां क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट यहां क्या करना है, इसमें बढ़ोतरी या घटोतरी क्या करना है, वह उसका करके हम चालू कर देंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मैं यह बात नहीं मानने वाला हूं। यों तो आप छापा लगाओ, मोहर लगाओ, मेरा पथ-प्रदर्शन करो कि भाई बलराम आप इतना कर चुके इसमें थोड़ा सा और डाल दो। मैं आप के लिए हाजिर हूं। आपको मेरा पूरा योगदान मिलेगा। किसान मांग करता है, किसान का राइट है, तो उसको भी अधिकार है। हमें देना चाहिए। बाकी सब जगह मिल चुका है। उसको स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिएं। उसको क्या नहीं चाहिए। मैं जब यहां के बच्चों को टमटम करते हुए देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूलों के बच्चे भी उसी तरह बैंचों पर बैठ करके कुछ पढ़ने की कोशिश

कर सकें और उनका मुकाबला कर सकें। मेरे वहां के बच्चे तो आई०ए०एस० वगैरह में आ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। यहां आपके पब्लिक स्कूल हैं, पैसे वाले स्कूल हैं। हम तो उन स्कूलों में पढ़े हैं जहां बस्ते में बोरी डाल करके स्कूल जाते थे। बैठने के लिए मां बोरी देती थी। वह भी हम लपेट करके आ जाया करते थे। वह कहती थी कि यह बैठने के लिए है और पता नहीं तुम जमीन पर कैसे लोट-पोट हो करके आ जाते हो। लेकिन आज तो यहां की जमीन पर पांव ही नहीं लगने देता। तो मैं थोड़ा सा उनके लिए भी चाहता हूं कि उनके चेहरे पर भी कुछ रौनक आए। उनके दिल में भी उमंग पैदा हो जो कि औरों के दिल में है। अब आपने टी०वी० लगा दिए। घर-घर में टी०वी० हैं। वह भी टी०वी० के पास जाकर देख लेता है तो वह भी चर्चा करता है कि सिकन्दर बख्त जी की तरह चांदनी चौक से गुजरे। तो यह सारी बातें मैं करना चाहता हूं जिसके लिए आप की सहायता की जरूरत है।

श्री जगेश देसाई: मंत्री जी, यह जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, रेन फेड एरिया है, पल्स सीड है, ऑइल सीड है और कोर्स फूड ग्रेन के बारे में आपने क्या किया?

श्री बलराम जाखड़: उसमें भी उसी प्रकार से हम करना चाहते हैं और सिवाय पल्सेस के आज हमारे पास तकरीबन-तकरीबन भगवान ने, हमारे किसान ने और हमारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सहायता की है जहां कि हम 50 मिलियन से 190 मिलियन पर पहुंच गए हैं। तिलहन में हम 12 मिलियन से 22.3 मिलियन पर पहुंच गए हैं। हमने उसका हिसाब लगाया है और हमें एक बूंद मंगवाने की भी कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ओ०जी०एल० का डिंढोरा इसलिए कर रखा है, मैं आप को बताना चाहता हूं कि जमाखोर होर्डिंग कर के वक्त-बे-वक्त उसका पैसा बढ़ा देते हैं। उसे रोकने के लिए यह किया है। जरूरत होती है तो उसको पंप कर देते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। दूध का उत्पादन बढ़ गया है, मछली का उत्पादन 7 लाख से 48 लाख पर आ गया है। कहीं कमी नहीं रखी है, लेकिन जहां तक सीरियल्स की बात है, कोर्स क्राप की बात है, उसमें कमी नहीं हुई है। ज्वार हमारे पास है, लेकिन कोई खानेवाला नहीं है। आपने गेहूं दे-देकर, चावल दे-देकर आदत बिगाड़ दी है। ज्वार कोई नहीं खाता, बाजरा कोई नहीं खता। पुराने जमाने में बाजारा खाया करते थे, लेकिन अब शान में फर्क पड़ता है बाजरा खाने से, हालांकि उस में ज्यादा इनग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटींस ज्यादा हैं, लेकिन उसे हजम करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, लेकिन पल्सेस हमारे पास कम है और हमारे पास ही नहीं सारी दुनिया में कम हुए हैं।

श्री के० आर० मलकानी (दिल्ली): पल्सेस कम है तो एक्सपोर्ट क्यों हो रही है?

श्री बलराम जाखड़: यह आप को गलतफहमी है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बाहर से मंगाकर उस को रूपांतर कर के वापिस कर सकता है, लेकिन यहां से कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एकाध पहले कहीं किसी ने की, मुझे इतना ज्ञान है कि उस को अंडरटेकिंग थी कि एक किस्म की जो हमारे हिंदुस्तानी भाई खाते हैं, उस को भेज कर उसके बजाय डेढ़ा आएगा तब उस को दी जाएगी और कोई बाहर जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। बाहर से मंगाने का सवाल जरूर है—आस्ट्रेलिया से, हंगरी से, थाईलैंड से और टर्की से जहां कि ये पैदा होती है। अब माजरा यह है कि रेन-फेड क्रॉप विकलजीकल क्रॉप है। इसमें पैसा ज्यादा लगता है। सूखा भी ज्यादा पड़ता है तो आमदनी कम होती है और आप जानते हैं कि किसान वह चीज बोता है जोकि उसे फायदेमंद हो। कोई दुकानदार भी ऐसी खेती नहीं करेगा जोकि नुकसान वाली हो क्योंकि अगर नुकसान करेगी तो दुकान नहीं चलेगी फिर हम भी किसान हैं और हम वह क्रॉप पैदा करेंगे जिस में फायदा होगा। आखिर हम किसी के बंधुआ मजदूर तो नहीं है। हम चाहते हैं कि हम मेहनत कर सकें और अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकें। इस के लिए हम ने इनसेंटिव दिया है और कीमत बढ़ायी है और 'ए क्रेस्ट' के साथ मिलकर एक कमीशन बनाया है सिर्फ पल्सेस के लिए। उन्होंने अरहर का बीज निकाला है, ड्वार्फ वेरायटी निकाली है, हायब्रिड निकाली है जोकि छोटा भी होगा और पकेगा भी जल्दी। अभी मैं परसों हैदराबाद से आया हूं। वहां "एक्रेसेट" से बात की थी, फिरोज साहब को और उनके साथी है, उनको बताया कि मिलकर ऐसा काम करें कि जिस में नए बीज की उत्पत्ति हो, ड्राउट रेसिस्टेंट हो, फल देने वाला हो, पेस्ट रेसिस्टेंट हो क्योंकि इस में जोखम बहुत जल्दी लगता है। यह सारा अड़ंगा होता है, फायदा कम होता है, इसलिए किसान इस की खेती कम करता है। हम इसे ज्यादा उत्पादन वाला बनाना चाहते हैं ताकि इस का लाभ आप को मिल सके। हालांकि आज हम 8 मिलियन से 14 मिलियन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह फिर भी कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह और ज्यादा हो।

यह सारी बातें इसमें हैं। आप विस्तार से इसे देख लीजिएगा और जो कुछ कमी लगे, मुझे बताइएगा। वह

मैं दूर करूंगा और आप को साथ लेकर किसान के माल को चमकाने का प्रयास करूंगा ताकि किसान यह कह सके कि मैं भी इस देश की प्रगति का भागीदार हूं। धन्यवाद।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से, डिवोशन से और भावनात्मक रूप से भारत सरकार की कृषि नीति को यहां रखा है। इस में हम सभी का सहयोग आप को मिलेगा, इस में दो राय नहीं है, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो आप की कृषि नीति है, वह ऐसी न लगे कि वह संसद या भारत सरकार की कृषि नीति है बल्कि वह ऐसी लगे कि भारत की कृषि नीति है, और इस बारे में मैं आप से विनती करना चाहता हूं कि देश के सभी भाषाई अखबारों में आप एक विज्ञापन निकालें सभी भाषायी पत्रों में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, जो भी गांव में जाता हो और उसमें आप किसानों से मांग करें कि इस तरह से भारत सरकार एक नीति निर्धारित करने जा रही है, आप किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, गांवों में रह रहे हैं, आप अपने सुझाव भेजिए। आप मानिए या न मानिए, लेकिन उनको इससे इतना अधिक संतोष हो जाएगा कि आप देखेंगे, लाखों लोग आपको पत्र भेजकर अपना इजहार करेंगे। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़: मैंने इस बात को पहले ही कहा कि हर प्रांत से, हर जगह से फार्मर्स को बुला बुलाकर, बात करके यह कराया है।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं अखबार में विज्ञापन की बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलराम जाखड़: विज्ञापन की बात नहीं, लेकिन मैंने हर क्षेत्र से, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो किसान, वह विरोधी विचार का हो या समर्थक हो, सबको बुलाकर, बात करके यह किया है। जैसा मैंने आप से कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत पालिसी नहीं है, यह किसान की पालिसी है, यह आपकी पालिसी है, सब की पालिसी है।

उपसभाध्यक्ष (कु० सरोज खापर्डे): डा० रणबीर सिंह।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडेन स्पीच।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैडम बैठी हैं और मैडेन स्पीच हो रही है।

डा० रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम वाइस चेयर परसन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की पालिसी के ऊपर बोलने का मौका दिया। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है और खेती के ऊपर निर्भर करती है। गांव की खुशहाली खेती की तरक्की से जुड़ी है और हिन्दुस्तान की तरक्की गांव की तरक्की से जुड़ी हुई है। मैं यह समझता हूं कि अगर खेती की तरक्की हो जाए तो हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है। खेती जहां आबादी का पेट भरने के काम आती है वहीं इंडस्ट्री को रा-मैटेरियल सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट के लिए मैटेरियल भेजती है, जिससे फारेन-एक्सचेंज देश के अन्दर आता है।

मैडम, खेती देश के हर पहलू के ऊपर असर डालती है। अगर खेती करने वालों की हालत सुधारी जाए तो उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, जरूरतें बढ़ने से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और उससे एम्पलायमेंट मिलेगी। मैं इसकी डिटेल में न जाकर अपनी बात की पुष्टि के लिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो अपनी वर्ष 1992-93 की बजट स्पीच में कहा था, उसका एक सेन्टेन्स दोहरा देना चाहता हूं—

> "Agriculture is the foundation of our national prosperity and no strategy of economic development can succeed in our country if it does not ensure rapid growth of production and employment in agriculture nor can we hope to provide sufficient jobs for our growing rural labour force unless we can transform the economy of our rural areas."

इसी बात को वर्ष 1994-95 के इकोनोमिक सर्वे में इस तरह से कहा गया है—

> "In overall economic development the agriculture sector will continue to lay a pivotal role since this sector still accounts for about 30 per cent of the GDP and almost two-thirds of the population still depends on this sector for livelihood."

मैडम, इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर खेती की अहमियत को समझा गया होता तो इसको सबसे ज्यादा प्रायरिटी देनी

चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती इस बात की रही कि आजादी के बाद खेती को उस प्रायरिटी का नहीं समझा गया और वह प्रायरिटी खेती को नहीं दी गई बल्कि देश में इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ ज्यादा सबकत दी गई और एग्रीकल्चर को महत्व नहीं दिया गया। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका ख्याल यह बना कि वह इस देश को इंगलैंड के मानचेस्टर की तरह से इण्डस्ट्रिलाइज कर दें। बस यही सबसे पहली भूल हो गई और यह भूल उसके बाद बकायदा दोहराते चले गए आज तक। 48 बरस हो गए हम लोगों को आजाद हुए लेकिन एग्रीकल्चर को जो प्रियारिटी मिलनी चाहिए थी वह आज भी इसको नहीं मिली। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक पालिसी बनाई है और उस पालिसी के तहत उन्होंने यह सोचा है कि देश के एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के बराबर लाएंगे, दूध में भी बढ़ोत्तरी करेंगे, लेकिन मेरे अपने ख्यालात हैं जो मैं बताना चाहूंगा और जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

जैसा मैंने पहले कहा कि जब हमें आजादी मिली तो शुरू में हमारे प्रधान मंत्री का ख्याल इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ गया। हालांकि अपने कार्यकाल के आखिरी हिस्से में उन्हें भी इस गलती का अहसास हो गया था लेकिन यह गलती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसको सुधारा नहीं गया और जैसा मैंने कहा, यह गलती आज भी दोहराई जा रही है। इसके सबूत में मैं फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का एक जुमला, जो उन्होंने 1995-96 के बजट में बोला था, उसको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:—"The inadequacy of public investment in agriculture is today a matter of general concern."
इसके बाद वे फिर कहते हैं:—"However, this is an area which is the responsibility of the States, who have neglected investment in infrastructure for agriculture."

तो आज तक यह हालत बनी हुई है कि आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चे का जो हाल है वह ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो पूरा एलोकेशन था, उसका 10 परसेंट एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिए किया गया था जो कि बहुत कम था 75-80 फीसदी आबादी के लिए और एग्रीकल्चर जैसा मैंने बताया कि 30 परसेंट जी०डी०पी० में जोड़ता है, उसके लिए 10 परसेंट इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। चौथी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाकर 12.9 परसेंट कर दिया गया, लेकिन यह भी बहुत कम था। इसके बाद सातवीं पचवर्षीय योजना में इस एलोकेशन को घटाकर 5.7 कर दिया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में तो इसको और भी घटाकर 5.2 परसेंट कर दिया गया। गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर इस अभाव का क्या असर पड़ा, उसमें कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 1957-58 में 18 करोड़ लोग थे जो पावर्टी लाइन से नीचे थे, 1973-74 में वे बढ़कर 22 करोड़ हो गए और 1993-94 में वे 35.48 करोड़ हो गए, जो करीब आबादी के 40 परसेंट लोग थे। एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर इसका क्या असर पड़ा? 1960-61 में जो एक मजदूर की आमदनी थी वह 552 रुपए थी और कॉस्टेंट प्राइस के ऊपर 1975-76 में घटकर वह 285 रुपए रह गई। रोड्स की हालत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में करीब 6 लाख गांव हैं, जिनमें से करीब सवा 3 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें सड़क नहीं है और 4 लाख से ज्यादा गांव ऐसे हैं हिन्दुस्तान के अंदर जिनमें फेयर वेदर में ही जाया जा सकता हो मानसून में या ऐसी हालत में, वह एक्सेसिबल नहीं है। लिट्रेसी की हालत यह है कि यू०पी० में 36.6 परसेंट लिट्रेसी है और इंडिया में 44.6 परसेंट लिट्रेसी है, यह गांव की हालत है और यह जो पालिसी हमारी रही है अब तक और जो नज़रिया रहा गवर्नमेंट का यह उसका नतीजा है। इसके साथ-साथ हेल्थ की बात मैं बता दूं। आपकी एक डिस्पेंसरी 49 हजार लोगों के लिए गांव में है और एक हास्पिटल 3 लाख लोगों के लिए गांव में है और एक हास्पिटल का बैड 8,500 लोगों के लिए देहात के अंदर है। इसके अलावा थोड़ा पैसा खेती में इन्वेस्ट होने के बावजूद भी, जो भी पैसा खेती को मिला, मैं यह देखता हूं कि वह भी पूरा खर्च नहीं हुआ, साल के बाद बहुत से महकमों का पैसा सरंडर हुआ है। खर्चा नहीं हुआ, थोड़ा पैसा मिला है, उसको भी खर्च नहीं किया गया और उसमें से भी पैसा बाद में सरंडर किया गया।

5 P.M.

हमको दरअसल जैसा माननीय मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी पौलिसी के तहत काम करना पड़ेगा अगर हमको गांव की हालत सुधारनी है। यहां के किसानों की हालत की स्टडी करनी पड़ेगी और हमको उसी के मुताबिक पौलिसी बनाकर टाईम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में 76.4 परसेंट छोटे और मार्जिनल किसान हैं।... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): डा० सिंह, जरा एक मिनट आप बैठेंगे।

I would like to take the sense of the House. I would like to know whether the House is ready to sit beyond 5 O'clock.

श्री संघ प्रिय गौतम: हां, यह कल किया जाए। आज तो यह पूरा नहीं होगा।

कुछ सम्मानित सदस्य: हां, यह अच्छा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): इसका मतलब है कि डा॰ सिंह अपना अधूरा भाषण कल कंटीन्यू करेंगे।

In that case, I adjourn the House till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd August, 1995.